अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–12 अंक–82 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ बुधवार 24 जुलाई 2024 पृष्ठ – 4 मूल्य–3 रूपया

संक्षिप्त समाचार

पति पर पत्नी को जहर देने का आरोप,जांच में जुटी पुलिस

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर में लवकुश नगर की नई बस्ती में पत्नी ने पति पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। परिजनों ने गंभीर हालत में महिला को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक कानपुर की रहने वाली महिला की लखनऊ के रहने वाले राशु से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों में विवाद होता रहता था। सोमवार को दोनों में विवाद हुआ। इसके बाद पति ने पत्नी को जहर दे दिया। जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। महिला की तबीयत बिगड़ने की जानकारी पड़ोसियों को लगी तो उन्होंने परिवार को सूचना देने के साथ ही आननफानन में महिला को लोहिया अस्पताल पहुंचाया। लोहिया अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है। फिलहाल गाजीपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस कर्मियों व उनके परिवार ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण, स्वस्थ रहने की मिली टिप्स

अलीगढ। अलीगढ़ में तैनात पुलिस कर्मी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, इसके लिए पुलिस लाइन में मंगलवार को स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। समाजसेवी संस्था के माध्यम से लाइन के अंदर कैंप लगा, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के लोगों ने अपनी जांच कराई। एसएसपी संजीव सुमन के निर्देश के बाद कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और उन्हें बताया गया कि वह समय–समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर कराएं। जिससे कि वर्तमान समय में होने वाली तमाम तरह की बीमारियों से वह खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने अपनी जांच कराई। स्वास्थ्य शिविर के दौरान पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उन्हें मानसिक तनाव से मुक्त रहने के भी टिप्स दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि आमजनों की सुरक्षा में तैनात जवान और पुलिस कर्मी 24–24 घंटे ड्यूटी करते हैं। जिले में चलने वाले तनाव और संवेदनशीलता के चलते कई बार वह छट्टियां भी नहीं ले पाते हैं। इसलिए उन्हें मानसिक तनाव हो जाता है। जवानों और पुलिस कर्मियों को मानसिक तनाव से दूर रखा जा सके, इसके लिए चिकित्सीय टीम की ओर से उन्हें टिप्स दिए गए हैं। जिससे वह मानसिक रूप से भी फिट रह सकें। सीओ थर्ड एएसपी अमृत जैन ने बताया कि प्रोजेक्ट उम्मीद के तहत मंगलवार को हेल्थ कैंप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मी 24–24 घंटे ड्यूटी करते हैं और उन्हें इस तरह के कैंप की काफी जरूरत है। इसमें प्राइवेट डॉक्टर भी अपनी फ्री सेवाएं दे रहे हैं। एएसपी ने बताया कि अभी पुलिस लाइन में कैंप लगाया गया है। लेकिन कई ऐसे पुलिस कर्मी हैं जो ड्यूटी पर तैनात हैं और कैंप में शामिल नहीं हो सके हैं। उनके लिए आने वाले दिनों में थाने में भी कैंप लगाया जाएगा। जिससे कि सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।

लखनऊ वासियों को अब मिलेगी अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी की सुविधा

मैक्स हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम द विंची एक्सआई का हुआ शुभारंभ'

लखनऊ। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने आज अत्याधुनिक द विंची शी रोबोटिक सर्जरी सिस्टम के शुभारंभ के साथ अपनी सर्जरी सुविधा के विस्तार की घोषणा की है। यह नई टेक्नोलॉजी लखनऊ के लोगों के लिए कम से कम चीरों वाली सर्जरी को और सुलभ बनाकर सर्जरी की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी।द विंची एक्सआई सर्जिकल रोबोट डॉक्टरों को छोटी चीरे के माध्यम से, उन्नत 3डी दृष्टि के साथ जटिल सर्जरी करने में सक्षम बनाता है, जिससे रोगी को होने वाली असुविधा और उनके अस्पताल में रहने की अवधी कम हो जाती है। सर्जन दा विंची शी सर्जिकल रोबोट उपकरणों का उपयोग करके सर्जरी कर सकते हैं जिन्हें वे कंसोल के जरिए से निर्देशित कर सकते हैं। लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, डॉ. गौरव अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट दृ हॉस्पिटल ऑपरेशन्स एवं जोनल हेड (वैशाली और लखनऊ), मैक्स हेल्थकेयर ने कहा, हम लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में नवीनतम दा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम लॉन्च करके बहुत उत्साहित हैं। यह हमारे मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार और चिकित्सा उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अत्याधुनिक तकनीक मैक्स हॉस्पिटल, लखनऊ की महत्वाकांक्षी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका लक्ष्य, चिकित्सा विज्ञान और रोगी देखभाल के क्षेत्र में अग्रणी बनकर, मैक्स हॉस्पिटल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। इस पहल से न केवल लखनऊ, बल्कि आसपास के इलाकों से भी मरीजों को सुविधा मिलेगी। यह न सिर्फ स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएगा, बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान

करेगा। डॉ. अग्रवाल ने कहा, ष्लखनऊ एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र है, जो न केवल राजधानी और आसपास के मरीजों को बल्कि पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश और बिहार के मरीजों को भी सेवाएं प्रदान करता है। दा विंची एक्सआई सिस्टम के लॉन्च के साथ, अब मरीजों को सर्वोत्तम उपचार प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी।यह तकनीक ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट मिनिमल एक्सेस, बेरियाट्रिक, गायनेकोलॉजी और सामान्य सर्जरी सहित विभिन्न चिकित्सा विभागों में सर्जरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रोबोटिक सर्जरी के फायदों के बारे में बात करते हुए, डॉ. राहुल यादव, डायरेक्टर – यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक यूरो–ऑन्कोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल, लखनऊ ने कहा, यह अत्याधुनिक तकनीक कम दर्द, कम रक्तस्राव, अस्पताल में रहने की कम अवधि, अपनी दैनिक जीवनचर्या और काम पर जल्दी लौटने और न्यूनतम जटिलताओं के साथ बेहतर रोगी परिणाम प्रदान करती है। द विंची रोबोटिक सिस्टम सर्जन को अद्भुत क्षमताएं प्रदान करता है। यह उनके हाथों की हरकतों को वास्तविक समय में कंसोल पर उतारता है, जिससे वे अत्यधिक सटीकता और गति के साथ जटिल ऑपरेशन कर सकते हैं। (मास्टर–स्लेव प्रणाली) मैक्स हॉस्पिटल, लखनऊ में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. शशांक चौधरी ने कहा, ऐसी उन्नत तकनीकों के कारण ऑन्कोलॉजी सर्जरी आम तौर पर 'निशान रहित' हो गई है। यह रोबोट सर्जन की निपुणता को बढ़ाता है और शरीर के उन हिस्सों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करता है जहां ऑपरेशन करना चुनौतीपूर्ण होता है। (सीने और पेलविस क्षेत्र में कैंसर होने पर बेहतर आंतरिक दृष्टि प्रदान करता है और इससे रक्तस्राव (हेमोस्टेसिस) को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है)। डॉ. शशांक चौधरी ने बताया, द विंची सिस्टम सर्जरी वाली जगह का अत्यधिक विस्तारित, 3डी हाई–डेफिनिशन दृश्य प्रदान करता है। उपकरणों का छोटा आकार सर्जन के लिए एक या कुछ छोटे चीरों के माध्यम से ऑपरेशन करना संभव बना देता है। वर्तमान में, मैक्स हेल्थकेयर देश के सबसे बड़े हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है, जिसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स में 24 रोबोटिक सिस्टम्स हैं। अब तक हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल्स में लगभग 10 हजार रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी हैं।

मोदी सरकार का बजट मायूस करने वाला ज्यादा : मायावती

लखनऊ,(यूएनएस)। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा सपा और

कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी–अपनी बातें कही। बसपा मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा, ष्संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्नासेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। उन्होंने आगे लिखा, देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहां के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा? इसके साथ ही बसपा प्रमुख ने पोस्ट में लिखा, देश का विकास व लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल–भुलैया वाला न हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसेआमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति–जरूरी। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे। इसके अलावा सपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि भाजपा ने जो आज बजट पेश किया है, इसने गरीब, किसान और नौजवानों को निराश किया है। अपने पुराने बजट जैसा 11वीं बार पेश किया है। इसमें बड़े लोगों को फायदा है। गरीबों और छोटे तबकों की उम्मीदों पर सरकार ने पानी फेरा है। यूपी की उपेक्षा लगातार 10 सालों से हो रही है। यही उत्तर प्रदेश ने इन्हें सबसे ज्यादा दो बार सांसद दिया। खुद पीएम यहीं से चुने गए हैं। लगता है यूपी ने इन्हें इस बार हरा दिया तो बदला ले रहे हैं। 2027 में इनको फिर उत्तर प्रदेश जवाब देगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट सिर्फ हवा–हवाई और किताबी है। बजट में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों की घोर उपेक्षा की गई है। शायद भाजपा 2024 में चुनाव में जो सीटों में घट गई हैं, इसकी वजह से वह युवाओं और आम आदमी से अपनी कुंठा बजट में निकाल रही है। इस बजट में किसी भी वर्ग को राहत नहीं दी गई है। बजट से देशवासियों को निराशा हाथ लगी है। देश के आम आदमी, किसानों, युवाओं के लिए मोदी सरकार को कोई चिंता नहीं है। यह बजट भी खोखला साबित हुआ, जिसमें की गई घोषणाएं बाद में गायब हो जाएगी।

एलडीए के पूर्व सचिव समेत चार को सजा, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला,

जानकीपुरम में जमीन घोटाला मामले में दोषी पाए गए

लखनऊ। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने एलडीए के पूर्व सचिव आरएन सिंह समेत 4 लोगों को सजा सुनाई है। तीन को 3 साल और एक को 4 साल की सजा सुनाई गई है। सभी पर कुल (1.25) लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकीपुरम जमीन आवंटन घोटाला मामले में चारों दोषी पाए गए है। इस मामले में कुल 7 आरोपी थे। दो की मौत हो चुकी है। जबकि एक को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश सीबीआई पश्चिम कोर्ट लखनऊ ने 1987–1999 के दौरान एलडीए की जानकीपुरम योजना के तहत जमीन आवंटन में अनियमितता मामले की सुनवाई कर रही थी। मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व सचिव आरएन सिंह को तीन साल का कठोर कारावास के साथ 35 हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं क्लर्क राज नारायण द्विवेदी को चार साल की सजा और 60 हजार का जुर्माना, साथी महेंद्र सिंह सेंगर व दिवाकर सिंह को तीन साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं एक को बरी कर दिया। सीबीआई ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के आदेश पर 21

फरवरी .2006 के आदेश पर 28 फरवरी 2006 को एलडीए के पूर्व सचिव आरएन सिंह सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन लोगों पर 1987 से 1999 के बीच एलडीए की जानकीपुरम योजना के 123 भूखंडों को अपने जानने वालों को आवंटित कर दिया। इस मामले में सीबीआई ने जांच पूरी कर 6 फरवरी 2010 को सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया एवं उन्हें सजा सुनाई। दो आरोपियों की मृत्यु के कारण उनका मुकदमा समाप्त कर दिया गया। वहीं एक को बरी किया गया।

अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करेगा बजट : योगी

किसानों की समृद्धि में बनेगा सहायक

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई संसद में वित्त मंत्री ने देश का जो आम बजट प्रस्तुत किया है वो सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख, 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024–25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। समाज के हर तबके के लिए बजट में किया गया प्रावधान रामराज्य की अवधारणा को साकार करने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2024–25 प्रस्तुत होने के बाद मीडिया से बातचीत में यह बातें कहीं। सीएम योगी ने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व उनकी टीम का अभिनंदन किया।सीएम ने कहा कि बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि, कृषि व सहायक सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये और महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया

गया है। इससे सर्वाधिक लाभान्वित देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी होने वाली है। खास तौर पर तब, जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ मध्यमवर्गीय परिवार के लिए इनकम टैक्स में नए टैक्स स्लैब की रियायत को स्वागत योग्य बताया। बोले कि यह बजट भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के आर्थिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मध्यमवर्गीय परिवारों को टैक्स में सबसे बड़ी छूट उपलब्ध हुई है। यह मांग लंबे समय तक चली आ रही थी। तीन लाख तक के इनकम टैक्स में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अन्य स्लैब भी राहत भरे हैं। अलग–अलग सेक्टर गांव–गरीब, किसान, नौजवान, इंडस्ट्री, एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए प्रावधान से लाखों नौकरियां सृजित होंगी। समाज के हर तबके के लिए बजट में किया गया प्रावधान रामराज्य की अवधारणा को साकार करने वाला है।

बिना सीएम के सम्पन्न हो गई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग

सीएम-डिप्टी सीएम की खटास कम करने में लगा आरएसएस

लखनऊ,। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच की खटास को आरएसएस अब कम करने में जुट गई है। पिछले दिनों आरएसएस के कई नेताओं की बैठकों ने इस ओर इशारा भी किया। बीते रोज लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर में संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम मिले लेकिन योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं थे। अमूमन बैठकों में सीएम मौजूद होते हैं। कुछ दिन पहले आरएसएस के दो नेताओं ने सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। वीएचपी नेता ने भी मौर्य से बात की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आरएसएस केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की खाई को भरने की कोशिश कर रहे हैं। खबर आई थी कि संघ के सरकार्यवाह अरुण कुमार लखनऊ आने वाले हैं और उसके बाद सबके साथ बैठक करेंगे, लेकिन नही आये। 2017 में भी ऐसा ही हुआ था जब केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच मनमुटाव हुआ था, आरएसएस के उस वक्त के बड़े अधिकारी दत्तात्रेय होसबोले योगी आदित्यनाथ को लेकर खुद केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी

आवास पर गए थे। साफ है कि पहले भी संघ मध्यस्थता करवा चुका है।एक तरफ कोशिश है कि बीजेपी में विवाद न बढ़े। दूसरी तरफ यह भी बातें उठ रही हैं कि 25 या 26 तारीख में दिल्ली में देशभर के सभी संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष संगठन के नेता संगठन के लोगों से मुलाकात करेंगे। धर्मपाल सिंह यूपी से मीटिंग में जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दूसरे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी शामिल हों सकते हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की सीएम योगी से मुलाकात हो सकती है।उत्तर प्रदेश खासकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के राह पर दुकानों और ढाबों पर नाम और नंबर लिखने का जो आदेश जारी हुआ था।सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदारों ने ढाबे वालों ने, फल वालों ने, जूस वालों ने भी नेम प्लेट अपनी दुकानों के बाहर से हटा दी है। योगी सरकार के आदेश के बाद जब हंगामा बढ़ा तो योगी सरकार ने बताया कि यह साल 2006 का फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट के तहत लागू कर दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों के आगे लाइसेंस और नाम लिखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि सरकार अभी देख रही है कि फैसले में क्या आया है और जो होगा सरकार उसका पालन करेगी।

सिडबी के सेंटर बढ़ने से मिलेगा फायदा,मुद्रा लोन की राशि बढ़ने से माइक्रो इंडस्ट्री को मिलेगा फायदा

लखनऊ। केंद्रीय बजट से वैसे तो यूपी के लिए कुछ खास ऐलान नहीं हुआ है लेकिन उसके बाद भी इस बजट से असर यहां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होगा।खासकर सिडबी के ब्रांच बढ़ाने और मुद्रा लोन की राशि 10 से 20 लाख रुपए से करने से युवाओं को माइक्रो इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा मंगलवार को आईआईए कार्यालय में संगठन से जुड़े लोगों ने चर्चा की। इस दौरान लोगों का कहना था कि बजट में यूपी के लिए कुछ खास नहीं है। हालांकि कुछ ऐसी घोषणाएं हुई है जिससे यहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बजट को लेकर एक्सपर्ट अदनान दानिश ने कहा कि सरकार ने बजट में यूपी के संदर्भ में कुछ खास नहीं किया। लेकिन कुछ स्कीम्स जरूर रही हैं। जो यूपी के किसानों के साथ उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होंगी। उन्होंने स्टार्टअप फॉर वेजीटेबल सप्लाई चेन का जिक्र करते हुए कहा कि यह किसानों के साथ उद्यमियों के हित का फैसला है। अदनान कहते हैं कि अगर मैं एक उद्यमी के तौर पर चाहूं तो अपना स्टार्टअप रजिस्टर करके एक गोडाउन बना सकता हूं। इसी तरह से किसानों के लिए नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी से लाभ होगा। यूपी में जो महिला उद्यमी हैं, वो अपने छोटे–छोटे कॉर्पोरेटिव बनाकर सब्सिडी और लोन का फायदा ले सकती हैं। इसी तरह से यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम काफी बदलाव लाने वाला होगा। आज हमारे 55 फीसदी यूथ के पास कोई स्किल नहीं है। अगर 20 लाख युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा तो युवाओं के लिए बेहतर होगा।

सम्पादकीय

दलित पिछड़ा निशाना है: मुसलमान तो बहाना है!

इस समय देश में दो यात्राएं चल रही हैं। एक अमरनाथ यात्रा जो पूरी मुस्लिम आबादी के बीच से होती हुई जाती है। दूसरी कांवड़ यात्रा जो अधिकांश हिन्दू आबादी के बीच से होती हुई निकलती है। जहां बीच–बीच में मिली–जुली आबादी भी है। अमरनाथ यात्रा सैकड़ों साल पुरानी है। तब भी नहीं रुकी जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। जम्मू से कश्मीर होकर जाने का ही मार्ग है। एक बार पाक समर्थित हिजबुल मुजाहिदीन ने यात्रा रोकने की धमकी दी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरा सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन जो कश्मीर में आतंकवाद शुरू करने वाला भी माना जाता है जेकेएलएफ (जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट) हिजबुल के सामने खड़ा हो गया। जेकेएलएफ ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके कहा कि हम यात्रा को सुरक्षा देंगे। और अगर हिजबुल ने कोई गलती करने की कोशिश की तो उसे इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यात्रा हुई। कश्मीर के मुसलमानों ने यात्रा का जबर्दस्त स्वागत किया। शान से हुई। और अभी भी चल रही है। रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त को खत्म होगी। यह है हमारे देश की मिलीजुली संस्कृति। हिन्दी हैं हमवतन हैं हिन्दोस्तां हमारा।

दूसरी तरफ इस बार कांवड़ यात्रा में खुद सरकार विवाद पैदा कर रही है। आजादी को रोकने के लिए अंग्रेजों ने जो हिन्दू पानी मुस्लिम पानी, हिन्दू चाय मुस्लिम चाय शुरू की थी। वह अब भाजपा सरकार कर रही है। कांवड़ यात्रा रूट पर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अपने खाने–पीने की दुकानों यहां तक की फलों के ठेले पर भी अपना नाम लिख कर टांगों।

जिस विभाजन को खत्म करके नेहरू ने भारत का नवनिर्माण किया था। उसे फिर बांटा जा रहा है। और यह यहां नहीं रुकेगा। मुसलमान की तो पहचान जगजाहिर है। उसके नाम से पता चलता है। और वह कभी छुपाता भी नहीं है। मगर दलित और पिछड़ों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। गांव से वह शहर इसीलिए आता है कि गांव में जाति के कारण उसे अलग थलग किया जाता है। प्रताड़ित भी। घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। मूंछें नहीं रख सकता। अभी कई जगह तो चप्पल पहनकर घर के सामने से निकलने पर बुरी तरह मारा गया और चप्पल सिर पर रखवाकर जुलूस निकाला गया।शहर में उसे यह समस्या नहीं है। कोई उसकी जाति नहीं जानता। लेकिन अब यह जो शुरूआत की है नाम लिखाने की भारतीय के अलावा और पहचान बताने की वह उसे खाने–पीने का कोई काम नहीं करने देगा। बाकी जगह नौकरी करने पर भी असर पड़ेगा। सरकारी नौकरियां तो खत्म कर दीं। दलित ओबीसी प्राइवेट में ही कर रहा है। या सरकारी दफ्तरों में भी ठेके पर। जहां जाति प्रमाणपत्र की कोई जरूरत नहीं है। कम तनखा और काम ज्यादा वही कर सकता है इसलिए उसे रखा जा रहा है। मगर अब पहचान उनसे भी पूछी जाएगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई दलित अपनी जाति नाम के साथ कोई ढाबा या खाने–पीने की रेहड़ी, ठेला भी लगा सकता है? मुसलमान तो होटल खोलता है ठेला भी लगाता है। कोई सफाईकर्मी अपनी जाति लिखकर एक छोटा सा खाने–पीने का ठेला भी लगाए तो सोचिए क्या होगा?

मुसलमान के यहां तो जाकर खाते हैं मगर उसके यहां खाना तो दूर ठेला ही उठाकर फेंक दिया जाएगा। सेना में चमार रेजिमेंट की मांग हो रही है। जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट की तरह। वह होना तो बहुत दूर की बात है। अगर वह अपने नाम से भुट्टा भी बेचने लगे तो वहां से भी उसे उठाकर भगा दिया जाएगा। मोदी मीडिया यूपी सरकार के इस फैसले का बड़ा समर्थन कर रहा है। पूछ रहा है कि आपत्ति क्या? वह एक रियलटी चेक कर ले। कांवड़ यात्रा मार्ग पर या कहीं भी एक चमड़े का काम करने वाले के नाम से, एक सफाई करने वाले के नाम से चाय–पकौड़े का, दाल–रोटी का या फल की ही सही एक–एक रेहड़ी लगाकर बैठ जाए। देखें क्या होता है? हां सावधानी के तौर पर डिस्केल्मर यह हम जरूर बता देते हैं कि आसपास पहले बाउंसर का इंतजाम जरूर कर लेना। नहीं तो जो नफरती भीड़ बना दी गई वह रेहड़ी तो फेंकेगी ही, मार–पीट भी करेगी। और उससे आगे भी जा सकती है। इसलिए मीडिया यह प्रयोग करे तो अपने रिस्क पर और बचाव के पूरे साधनों के साथ। पुलिस को भी हम सावधान करना चाहते हैं कि वह भी नफरती भीड़ के सामने होशियारी से आए। यूपी में ही कई जगह पुलिस के बड़े अफसरों पर हमला हुआ है। एक इंसपेक्टर सुबोध कुमार सिंह की तो हत्या ही कर दी थी। और आरोपियों को न केवल जमानत मिल गई बल्कि बीजेपी में पदाधिकारी भी बना दिया गया। छह साल हो गए हैं अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। नफरत देश को कहां ले जाएगी। पता नहीं। आजादी के लिए लड़ने वालों ने इस नफरत से लड़ते हुए ही देश को एक रखा है। लाल किले में आजाद हिंद फौज के क्रान्तिकारियों का ट्रायल शुरू होने वाला था। सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज अंग्रेजों की आंख के कांटे यहीं थे। नेहरू जिसे ये इतना बदनाम करते हैं उन्होंने इन क्रान्तिकारियों का मुकदमा लड़ने के लिए मुद्दत बाद वापस अपना वकालत वाला काला कोट पहना था। गांधी उनसे मिलने गए। तो बातों में मालूम पड़ा कि वहां सुबह हिन्दू चाय–मुसलमान चाय अलग– अलग आती है। गांधी ने पूछा फिर आप क्या करते हो। उन्होंने बताया कि हम एक बर्तन में दोनों मिला लेते हैं। और फिर मिल बांट कर पी लेते हैं। कर्नल ढिल्लन ने अपनी आत्मकथा फ्रम माय बोन्स में लिखा है कि महात्मा गांधी इतने खुश हुए कि बोले अब अंग्रेज ज्यादा दिन यहां नहीं रह सकते। मगर अब फिर उसी विभाजनकारी दौर को लाने की कोशिश की जा रही है। याद है कोरोना जब शुरू था तो मुसलमानों पर आरोप लगाया गया कि वे थूक जिहाद कर रहे हैं। कई पत्रकारों ने एंकरों ने लिखा बोला कि हमने उन्हें थूकते हुए देखा है। तब्लिगी जमात के कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर कोरोना फैलाने के आरोप लगाए।

हमने उसी समय 2 अप्रैल 2020 को लिखा था कि कोरोना से लड़ो उसमें हिन्दू–मुसलमान न करो। झूठ और नफरत मत फैलाओ। कोरोना से लड़ाई कमजोर होगी। वही हुआ। उस लेख का शीर्षक था–कोरोना को हरा नहीं बनाओ! लेकिन पूरी ताकत उसमें लगा दी। इलाज, इंजेक्शन, दवाइयां, अस्पताल, आक्सीजन सब भूल गए। शव पुलों से नीचे फेंके गए। नदियों में बहाए गए। मगर हिन्दू–मुसलमान जारी रखा। क्या हुआ? लाखों मर गए। अब वैक्सिनेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। युवा अचानक गिर कर मर रहे हैं। और फिर अभी पिछले महीने कोर्ट का फैसला आ गया। तब्लिगी जमात पर लगे सब आरोप गलत साबित हुए। सब आरोपियों को बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन झूठ फैलाना था। फैला दिया। अब फिर वैसे ही थूक की और दूसरी घृणित कहानियां चलाई जा रही हैं। अच्छी सरकार लोगों के स्तर को ऊपर ले जाती है। पढ़ाई–लिखाई, नौकरी, स्वास्थ्य, अच्छे जीवन की बातें होती हैं। नफरती सरकारें थूक और उससे भी अशोभनीय चीजों को चर्चा का केन्द्र बना देती है। पिछले दस साल में जितना शब्द गोबर लिखा और बोला गया है पिछले सौ सालों में भी नहीं।

अभी बांग्लादेश में हुए छात्र पुलिस संघर्ष के बाद पता चला कि सैकड़ों भारतीय छात्र भी वहां से वापस आए हैं। यह हाल कर दिया हमारी शिक्षा व्यवस्था का। भारतीय छात्र पढ़ने छोटे –छोटे देशों में जा रहे हैं। लड़ाई थी मोदी और योगी की। लोकसभा चुनाव के कमजोर रिजल्ट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। कौन बड़ा है? कौन रहेगा? भविष्य किसका है? संघ किसके साथ है? लेकिन जैसा अंग्रेज करते थे हर सवाल का जवाब हिन्दू–मुसलमान में ढूंढने की कोशिश करते थे। असफल हुए। जाना पड़ा। वैसे ही अब ये सरकारें कर रही हैं।

नेपाल की नयी सरकार के साथ खुले दिमाग से पेश आना होगा

नेपाल में सीपीएन (यूएमएल)नेता केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में एक नयी सरकार ने सत्ता संभाली है। ओली 21 जुलाई को संसद में विश्वास मत हासिल करने के लिए तैयार हैं। साथ में सीपीएन (यूएमएल)और नेपाली कांग्रेस के गठबंधन के पास निचले सदन में कुल 167 सीटों के साथ एक आरामदायक बहुमत है, जो 138 सीटों की आवश्यक सीमा को पार कर जाता है। इससे ओली का विश्वास मत एक सीधी प्रक्रिया प्रतीत होती है। नेपाल, एक छोटा सा भू–आबद्ध देश है जो अपने ऊंचे हिमालय पर्वतों के लिए जाना जाता है। यह देश भारत और चीन के बीच अपने रणनीतिक स्थान के कारण भी महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक महत्व रखता है इसलिए दोनों देश नेपाल में अपने–अपने प्रभाव के लिए होड़ करते हैं। भारत नेपाल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राजनयिक मिशन रखता है, जो नेपाल के सामरिक महत्व और देश के मामलों में भारत की गहरी रुचि को रेखांकित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय देश नेपाल में होने वाले घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखते हैं, क्योंकि वे इस क्षेत्र की भू–राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, चीन भी नेपाल में अपने प्रभाव को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है, खास तौर पर विभिन्न बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के जरिए। 2015 की घटना के नेपाली संस्करण के अनुसार, भारत ने उस वर्ष नेपाल पर आर्थिक नाकेबंदी लगाई थी, तथा भारत की सीमा से लगे मैदानी इलाकों में रहने वाले मधेसी समुदाय पर नये संविधान के प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई थी। इस नाकेबंदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया था, लेकिन कई महीनों के बाद इसे हटा लिया गया, जिससे नेपाली जनता की भावना में अधिक संतुलित विदेश नीति दृष्टिकोण की ओर बदलाव आया। केपी शर्मा ओली ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, लेकिन भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद, अपने कार्यकाल के दौरान चीन की ओर झुकाव के लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके प्रशासन ने चीन के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये, हालांकि भारत तक आसान पहुंच की तुलना में नेपाल के कठिन भूभाग द्वारा उत्पन्न रसद चुनौतियों के कारण कई समझौते अभी तक मूर्तरूप नहीं ले पाये हैं। ओली के चीन समर्थक रुख से असंतुष्ट होने के बाद, उनकी सरकार की लोकप्रियता कम हो गई, जिसके कारण 2019 में उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। इसके बाद, पुष्पकमल दहल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (यूएमएल) के समर्थन से प्रधानमंत्री की भूमिका संभाली, तथा अपने कार्यकाल के दौरान वह कई अविश्वास प्रस्तावों से निपटे। अब केपी शर्मा ओली के सत्ता में लौटने के साथ, इस क्षेत्र के देश बड़ी बारीकी से देख रहे हैं कि उनका नेतृत्व नेपाल के नाजुक भू–राजनीतिक संतुलन और भारत और चीन के साथ उसके संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा। उनका आगामी विश्वास मत आने वाले महीनों में नेपाल के शासन की स्थिरता और दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा। नेपाल में एक नई सरकार को एक गंभीर दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जो बेरोजगारी और शिक्षा जैसे पुराने मुद्दों को संबोधित करे। स्थायी समाधान की कुंजी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और पर्याप्त निवेश में निहित है। नेपाल के शासन में राजनीतिक अस्थिरता की विशेषता रही है, जो राष्ट्र निर्माण और संस्थागत विकास और आर्थिक प्रगति में बाधा डालती है। स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए नागरिकों, नीति निर्माताओं और हितधारकों की ओर से धैर्य और प्रतिबद्धता के साथ भागीदारी की आवश्यकता होती है। नेपाल की भविष्य की सफलता के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना और यथार्थवादीअपेक्षाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, मीडिया और बुद्धिजीवी अक्सर राजनीतिक घटनाक्रमों को सनसनीखेज बनाते हैं, अस्थिरता को बनाये रखते हैं, और राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लक्ष्यों से ध्यान भटकाते हैं। नेतृत्व परिवर्तन का आवर्ती चक्र, जिसका उदाहरण केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में हुए बदलाव हैं, निरंतर चुनौती को दर्शाता है। केवल भू–राजनीतिक पैंतरेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, नेपाल की समृद्धि का मार्ग आंतरिक चिंतन और एक दशक या उससे अधिक समय तक जमीनी स्तर पर निरंतर प्रयासों पर टिका है। तभी जाकर नेपाल पड़ोसी भारत के साथ संबंधों जैसे बाहरी चिंताओं से सार्थक रूप से जुड़ सकता है। भारत नेपाल में नई सरकार के गठन को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखेगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिनमें अपार संभावनाएं हैं। नेपाल का ऊर्जा परिदृश्य, विशेष रूप से जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा में, सहयोग के लिए आशाजनक रास्ते प्रस्तुत करता है। भारत की पर्याप्त बिजली की मांग को देखते हुए, नेपाल की जलविद्युत क्षमताओं का दोहन पारस्परिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा, नेपाल के माध्यम से रेल मार्ग जैसी रणनीतिक अवसंरचनात्मक परियोजनाएं भारत के उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं, जो चल रही पहलों का पूरक है। ईको–टूरिज्म द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक और आशाजनक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। नेपाल अन्नपूर्णा रेंज जैसे प्राचीन स्थलों की पेशकश करता है, जो उच्च–बजट वाले यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। नेपाल के पर्यटन बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देकर भारत को लाभ होगा। आर्थिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं, यह इस बात से स्पष्ट है कि नेपाल भारत को धन भेजने वाला सातवां सबसे बड़ा देश है। आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने से छोटे–मोटे विवादों को सुलझाने से परे पर्याप्त पारस्परिक लाभ मिल सकते हैं। इसलिए, नेपाल के पर्यटन बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने से भारत को लाभ होगा। दोनों देशों को विवादास्पद मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय आर्थिक तालमेल को अधिकतम करने की दिशा में काम करना चाहिए।नेपाल में नये प्रशासन के आने के साथ ही, आर्थिक समृद्धि और रणनीतिक सहयोग पर आधारित संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। द्विपक्षीय मुद्दों को संबोधित करने के अलावा, नेपाल क्षेत्रीय संघर्षों में मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण क्षमता रखता है। भारत और चीन के बीच टकराव अक्सर सुर्खियों में रहता है। नेपाल की संघर्षरत दलों के बीच शांति को बढ़ावा देने की क्षमता एक आकर्षक संभावना है। भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया का भू–राजनीतिक परिदृश्य नेपाल की सर्वसम्मति निर्माता के रूप में संभावित भूमिका को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए, पिछले तीन वर्षों में म्यांमार के स्थायी सैन्य शासन और नागरिक अशांति और बांग्लादेश में रोहिंग्या संकट के बीच हस्तक्षेप की आवश्यकता है। शांति सुविधाकर्ता के रूप में काठमांडू का उभरना एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। भारत और चीन के बीच रास्ता बनाने के अपने वर्तमान जुनून को पार करने के लिए, नेपाल को अपने अंतरराष्ट्रीय कद और जुड़ाव को व्यापक बनाना होगा। क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़ते हुए, काठमांडू को अपने निकटतम पड़ोसियों से परे भी गठबंधन तलाशना चाहिए। यह रणनीतिक बदलाव नेपाल को वैश्विक मंच पर उभार सकता है, तथा उसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है।

संसद सत्र: कठघरे में होगी सरकार

सोमवार से प्रारम्भ होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में नयी सरकार की बड़ी घेराबन्दी तय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर कदमों से सरकार के रूप में संसद भवन पहुंची है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबन्धन 2014 एवं 2019 की तुलना में बड़े आकार, एकजुटता और बढ़े हुए मनोबल के साथ संसद के दोनों सदनों में दहाड़ मारने को तैयार है। लोकसभा का पहला सत्र 22 जून से 2 जुलाई और राज्यसभा का सत्र 27 जून से 3 जुलाई तक हुआ था, जिसमें विपक्ष अपने दम की झलक दिखा चुका है। इस बीच राज्यसभा में भाजपा व उसके सहयोगी गठबन्धन नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस का घटा हुआ बहुमत सत्ताधारी दल को बैकफुट पर बैटिंग करने को मजबूर करेगा। पिछले सत्र में नीट परीक्षा के पेपर लीक का मामला जोर–शोर से उठा था, जो अब भी गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नतीजे घोषित करने के आदेश के सन्दर्भ में सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई तो रहेंगी ही, अन्य और भी कई मुद्दे सरकार को परेशान करते रहेंगे। 12 अगस्त तक इस सत्र के चलने की सम्भावना है। मंगलवार को आम बजट पेश किया जायेगा जो नयी सरकार का पहला बजट होगा। इसे मोदी सरकार की पहली परीक्षा बतलाई जा रही है। भाजपा सरकार जिन दो दलों के समर्थन पर मुख्यतया टिकी हुई है, वे दोनों ही केन्द्र सरकार से भारी–भरकम आर्थिक पैकेजों की अपेक्षा कर रहे हैं। आंध्रप्रदेश की तेलुगु देसम पार्टी और बिहार का जनता दल यूनाइटेड क्रमशरू 16 तथा 12 सांसदों के साथ इस उम्मीद से समर्थन दे रहे हैं कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जायेगा। हालांकि अब राज्य की यह श्रेणी एक प्रकार से अस्तित्व में नहीं रह गई है लेकिन उसकी भरपाई अगर बड़ी राशि प्रदान करने से होती है तो अन्य राज्यों में सरकार एवं भाजपा के प्रति असंतोष बढ़ेगा, विशेषकर जिन राज्यों में भाजपा को शानदार सफलता लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मिली है। ये राज्य हैं– छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओडिशा आदि। यदि उनके साथ भेदभाव हुआ तो पार्टी अनुशासन के चलते इसकी खुली प्रतिक्रिया चाहे न हो, लेकिन असंतोष बढ़ेगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिये टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार को साधना चुनौती रहेगी। यह सत्र ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जब न सिर्फ सरकार कमजोर है, बल्कि हाल के कई घटनाक्रम इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि नरेन्द्र मोदी और उनके मुख्य सिपहसालार यानी केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संगठन पर पकड़ छूटती जा रही है। अनेक नेताओं के बयान इस बात की गवाही दे रहे हैं। हालांकि स्थिति फिलहाल विस्फोटक तो नहीं कही जा सकती लेकिन यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा कि दोनों पहले संगठन पर और फिर सरकार पर अपना नियंत्रण खो बैठेंगे। हाल ही में कुछ नेताओं ने जिस प्रकार की बयानबाजियां की हैं वे या तो पार्टी की घोषित नीति के खिलाफ हैं या फिर उनके तीरों की दिशा मोदी–शाह की ओर है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किये जा रहे कुछ कार्यक्रम भी यही बता रहे हैं कि मोदी–शाह की जकड़ अब संगठन पर वैसी नहीं दिख रही है जो कुछ समय पहले तक थी। बहुत सम्भव है कि संसद के तकरीबन 20 दिन चलने वाले इस मानसून सत्र में इस बात के और भी सबूत मिलें जिस दौरान सरकार का सामना पहले से कहीं अधिक मजबूत विपक्ष के साथ–साथ अपने ही असंतुष्ट सहयोगियों से होने जा रहा है। शुरुआत करें तो, पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेन्दु अधिकारी ने एक भाषण में कहा कि भाजपा को सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा छोड़ देना चाहिये। उनका इशारा भाजपा की मुस्लिमों को साथ लेने की कभी–कभार की जाने वाली कोशिशों की तरफ था। उनका बयान भाजपा के सहयोगी दल टीडीपी को भी नाराज कर सकता है जिसने मुस्लिमों के हक में कई कल्याणकारी कार्यक्रम लाने का ऐलान कर हालिया चुनावों में जीत दर्ज की है। ऐसे ही, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रियों के रास्ते में लगने वाली दुकानों पर मालिकों को अपने नाम लिखने सम्बन्धी जो फरमान जारी किया गया है, वह भी मोदी सरकार की विपक्ष द्वारा ही नहीं वरन कुछ सहयोगी दलों द्वारा भी घेराबन्दी करने के लिये एक माकूल विषय हो सकता है। उल्लेखनीय है कि भाजपा के सहयोगी एवं एनडीए के घटक दल यथा राष्ट्रीय लोक दल, जेडीयू, एनसीपी आदि ने इस निर्णय की आलोचना कर इस निर्देश को वापस लेने का आग्रह किया है। टीडीपी, लोक जनशक्ति पार्टी, एनसीपी (अजित पवार गुट) जैसे दल इसे लेकर अपने मतदाताओं के सामने शर्मिन्दा हो सकते हैं जो धर्मनिरपेक्षता की नीति पर चलते हैं। यह आदेश न केवल साम्प्रदायिकता को बल्कि जातिवाद को भी बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। इस समय मोदी के साथ उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ की रस्साकशी जारी है। यह मुद्दा जोर–शोर से इस सत्र में उठेगा ही। देखना होगा कि मोदी इसे कैसे हैंडल करते हैं क्योंकि यह मामला सहज नहीं है। यदि इस निर्णय को मोदी गलत बताते हैं तो हिन्दुत्ववादी मतदाताओं में योगी का कद उनसे बड़ा हो जायेगा। वैसे भी अब तो प्रधानमंत्री पद के लिये योगी भाजपा समर्थकों के बीच मोदी से बेहतर माने जा रहे हैं। बेशक संसद का सत्र मोदी एवं उनकी सरकार के लिये मुश्किलों भरा होगा।

संविधान नहीं विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक खतरे में

इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल केंद्र की भाजपा सरकार पर संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। मोदी सरकार ने इसके जवाब में विपक्ष पर सीधे हमला बोलते हुए 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपात्तकाल के दिन 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में सरकारी स्तर पर मनाने का फैसला कर दिया। दरअसल विपक्ष जिसे संविधान खत्म करने की साजिश बता रहा है, वह दरअसल मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने की कवायद है। तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने अभी तक एक भी ऐसा काम नहीं किया है, जिससे लगता हो कि सरकार के इरादे संविधान को खत्म करने के हैं। इस संबंध में विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, वह दरअसल संविधान खतरे में नहीं बल्कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खतरे में पड़ गया है। विपक्ष इसे सीधे स्वीकार नहीं करके संविधान खात्मे की संज्ञा दे रहा है। केंद्र सरकार ने जब–जब देश के मुस्लिमों की भलाई के लिए निर्णय लिया और कानून बनाया तब–तब विपक्षी दलों ने कठमुल्लओं की भाषा बोलते हुए इसका विरोध किया है। मुस्लिम सुधारों के इस प्रयास को ही गैर भाजपा विपक्ष संविधान को खत्म करने की साजिश करार दे रहा है, हिन्दू वोट बैंक के भय से इस पर खुल कर बोलने से बच रहा है। यही वजह है कि भाजपा गठबंधन लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी विपक्ष एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सका जिससे लगे कि देश का संविधान या आम लोगों को अधिकार खतरे में हैं। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को अधिक और कानूनी बराबरी के अधिकार सम्पन्न बनाने का ही काम किया है। यह विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है।

17 वीं लोकसभा के दौरान मणिपुर हिंसा के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी। संसद की कार्रवाई लगातार बाधित करने के कारण तत्कालीन 140 विपक्षी सांसदों की सदस्यस्ता निलंबित की गई। विपक्ष ने इस घटना पर भी संविधान के खात्मे की दलील दी। इसके विपरीत हाल ही में तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया, इस पर इंडिया गठबंधन के दल मौन साधे रहे।

केंद्र सरकार ने मुस्लिमों और देश की एकता–अखंडता को लेकर किए गए सकारात्मक प्रयासों को विपक्षी दलों ने अल्पसंख्यक वोट बैंक के नजरिए से देखा है। तीन तलाक को गैरकानूनी बनाने के लिए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 के पक्ष में सबसे ज़्यादा वोटिंग के साथ पारित होने पर कांग्रेस ने विरोध स्वरूप वॉकआउट किया। इससे पहले जनता दल (यूनाइटेड) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों ने भी तत्काल तलाक को अपराध बनाने वाले बिल के विरोध में वॉकआउट किया था। इस कानून को बनाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे।

कांग्रेस गठबंधन के कई दलों ने एक कदम आगे बढ़ कर केंद्र में सत्ता में आने पर तीन तलाक को प्रतिबंध करने के कानून को खत्म करने का वादा किया था। इससे साफ जाहिर है कि विपक्षी दलों की मंशा मुस्लिम महिलाओं को पाषाण युग जैसा जीवन जीने के लिए अभिशप्त करने की रही। गौरतलब है कि शाहबानों वाले मामले में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक बनाए रखने के लिए कानून में संशोधन करके इस आदेश को रद्द कर दिया था।

इसी तरह केंद्र सरकार ने जब जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद की धारा ३७० हटाने का निर्णय लिया, तब भी विपक्षी दलों को मुस्लिम वोट दरकता नजर आया। विपक्षी दलों ने देश की एकता–अखंडता को मजूबत करने और जम्मू–कश्मीर को तरक्की के रास्त पर ले जाने वाले इस कानून का भरसक विरोध किया। यह बात दीगर है कि इस कानून के हटने के बाद जम्मू–कश्मीर विकास के मामले में बुलंदी छू रहा है। धारा ३७० हटने से पहले देश से कटा यह राज्य अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। विदेशी निवेश के साथ पर्यटन तेजी बढ़ रहा है। केंद्र ने एम्स बनाने की घोषणा की है।

मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर भी विपक्षी दलों को मानों सांप सूंघ गया हो। इस निर्णय के मुताबिक कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ता मिले की हकदार है। इस वजह से वह गुजारे भत्ते के लिए याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण–पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने एक प्रस्ताव पास करके विरोध किया। बोर्ड ने इस फैसले को इस्लामिक कानून (शरीयत) के खिलाफ बताया। देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और अधिकार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना तो दूर बल्कि विपक्षी दलों ने चुप्पी साध ली, कहीं समर्थन करने से कठमुल्ले मुस्लिमों को उनके खिलाफ भड़का कर वोट बैंक का नुकसान नहीं कर दें।

मुस्लिमों के लिए किए गए इन तमाम सुधारों के प्रयास विपक्षी नेताओं को खटकते रहे हैं। विपक्ष ने इन प्रयासों के विरोध को ही संविधान के खात्मे का प्रयास माना है, किन्तु खुल कर ऐसा कहने से कतराते रहे हैं। कांग्रेस के शासन के दौरान देश भर में आतंकी बम धमाके करते रहे, तब विपक्षी दलों को संविधान खतरे में नजर नहीं आया। कारण साफ था ज्यादातर धमाकों से जुड़े आरोपी मुस्लिम थे, इनकों विपक्षी दल किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं मौके–बेमौके पर विपक्षी दलों ने माफिया डॉन को महज इस कारण समर्थन किया कि वे मुस्लिम हैं। उन्हें टिकट देकर विधायक–मंत्री तक बनाया। उत्तर प्रदेश और बिहार के माफिया इसका उदाहरण हैं। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने आंसू बहाए थे। इससे ही साबित होता है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए विपक्षी नेता देश के कानून–संविधान से किस हद तक खिलवाड़ करने वालों का साथ दे सकते हैं।

कांवड़ यात्रा विवाद

सावन के माह में शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा का लंबा पौराणिक इतिहास रहा है। आस्था के साथ इसका सांप्रदायिक सौहार्द का पक्ष भी सबल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के एक हालिया आदेश से एक अनावश्यक विवाद को बल मिला है। दरअसल, प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि कांवड़ मार्गों पर सभी खाद्य व पेय पदार्थों की दुकानों तथा होटलों के संचालकों व मालिकों को अपना नाम व पहचान प्रदर्शित करनी होगी। दलील दी गई है कि कांवड़धारियों की आस्था की पवित्रता को बनाये रखने तथा कांवड़ियों की शांतिपूर्ण आवाजाही सुनिश्चित करने के लिये आधिकारिक तौर पर यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल–प्रमाणित उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों के नेताओं व अन्य संप्रदायों के लोगों ने आदेश को अल्पसंख्यकों को अलग–थलग करने की कोशिश बताया है। दरअसल, एक पखवाड़े से अधिक समय तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों और दुकानदारों के बीच अक्सर हिंसा देखने में आती रही है। जिसकी मुख्य वजह यह रही है कि कांवडियों और दुकानदारों के बीच मांसाहारी भोजन को लेकर बहस व विवाद होता रहा है। यही वजह है कि अगस्त, 2018 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान भड़की हिंसा व टकराव में निजी व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया था। इतना ही नहीं, वर्ष 2022 में हरिद्वार में हरियाणा के कांवड़ियों के साथ हुए विवाद में सेना के एक जवान की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।निस्संदेह, कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार के टकरावों से बचने के लिये राज्

सफेद रंग की अपाचे बाइक सवार तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतर कर जन सेवा केंद्र संचालक के डेढ़ लाख रूपयों की संदीप सिंह के होटल के पास की लूट, लूट को लेकर क्षेत्र में जगह-जगह चर्चा

अवध की आवाज ब्यूरो
गुड्डू मिश्रा ब्यूरो

उन्नाव। जनपद उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अचलगंज थाना क्षेत्र निवासी शिवम बाबा खेड़ा चौराहा रायबरेली रोड पर जन सेवा केंद्र चलता है वह दिनांक 22.7.2024 समय 22:15 बजे वह अपने जनसेवा केंद्र से अपनी दुकान बंद कर अपनी मोटरसाइकिल अपाचे से घर की तरफ जा रहा था साथ में एक काले रंग के बैग में डेढ लाख रुपए तथा दो एटीएम कार्ड व एक क्रेडिट कार्ड था जैसे ही वह संदीप सिंह के होटल बहद ग्राम पोटरिहा पहुंचा तो पहले से खड़े सफेद रंग की अपाचे बाइक सवार तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरकर पीछे से सर पर वार कर दिया जिससे वह घायल हो गया घटना कर्ताओं ने कमर पर टंगे बैक को छीन कर भाग गए। सूचना पर जनपद के पुलिस अधीक्षक सहित सभी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच शुरू कर दी।

राम मंदिर में पुजारियों के लिए जारी किए गए रोस्टर पर रोक, पहले की तरह ही होगी पूजा

राम मंदिर में पुजारियों के लिए जारी किए गए रोस्टर पर रोक लगा दी गई है और पहले की तरह ही पुराने पुजारियों के साथ नए पुजारी रामलला की पूजा करेंगे।

लखनऊ। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के पुजारियों के लिए जारी किए गए रोस्टर पर रोक लगा दी गई है। पुजारी पहले की तरह ही रामलला की पूजा करेंगे। रोस्टर पर पुजारियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी।

राम मंदिर में पुजारी अपने निर्धारित समय से पूजन पद्धति को संपन्न कर रहे हैं। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि सभी पुजारियों के द्वारा ट्रस्ट को दिए गए पत्र के बाद ट्रस्ट ने अपने निर्णय को वापस ले लिया है। अभी सभी पुजारी पहले के समय पर राम मंदिर में सेवा देंगे।

बताते चलें कि श्रावण माह को लेकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारी के साथ बैठक कर चार समूह में पुजारियों को विभक्त कर श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित राम मंदिर, कुबेर टीला और यज्ञशाला स्थल पर 10 घंटे की सशर्त ड्यूटी लगाई है। जिसमें बताया गया कि जिस पुजारी की ड्यूटी जिस स्थान पर लगाई गई है अगले 15 दिन तक वह दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेंगे, यानी कि कुबेर टीला और यज्ञशाला पर तैनात पुजारी अगले 15 दिन तक राम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जिसको लेकर सभी पुजारियों ने आपत्ति जताई थी जिसके बाद सोमवार को ट्रस्ट ने नई व्यवस्था पर रोक लगा दी है।

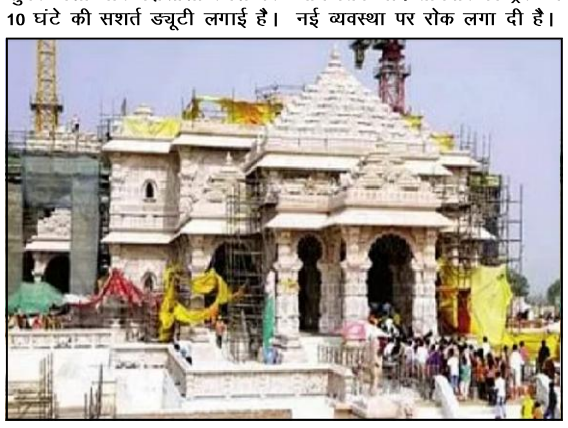

भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, कार्रवाई में जुटी पुलिस

बांदा।बांदा से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। जिसमें भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया है। घायल पूर्व मंडल अध्यक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह दबंगों के ऊपर कार्रवाई के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला नरैनी कोतवाली क्षेत्र का है। जिसमें पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया। वीडियो में घायल प्रदीप सिंह सेंगर ने बताया कि दबंग रामबाबू श्रीवास ने उन पर जानलेवा हमला किया है। उसके ऊपर पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। घायल प्रदीप सिंह सेंगर ने दबंग के ऊपर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि दबंग ने उन पर हमला कर घायल कर दिया। फिर प्रदीप के दोस्तों के द्वारा उन्हें पुलिस थाने ले जाया गया। जहां पर उन्हें अस्पताल के जाया गया। जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिए हुए जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

फाइन आर्ट गैलरी एंड सोशल वेलफेयर संस्था द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम

अवध की आवाज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर महानगर में फाइन आर्ट गैलरी एंड सोशल वेलफेयर संस्था द्वारा आर्य नगर परशुराम वाटिका में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन जी, रामपाल जी, गीता जी, और आदि लोग उपस्थित रहे, प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन जी ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पीपल, नीम, बरगद, जैसे पेड़ों को लगाने का संदेश दिया।

जन सेवा केंद्र संचालक को पीटकर 1.50 लाख लूटे, बाइक सवार तीन लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम

कोतवाल प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ित का प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसे कोतवाली लाया गया था। उसकी तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच चल रही है।

उन्नाव। उन्नाव जिले में जनसेवा केंद्र बंद कर घर जा रहे संचालक को उन्नाव–रायबरेली हाईवे के बाबाखेड़ा के पास सोमवार रात अपाचे बाइक सवार तीन बदमाशों ने जमकर पीटा और उसके पास रही 1.50 रुपये नगदी लेकर भाग निकले। घटना की सूचना पर एसपी, एएसपी दो सीओ और तीन थानों का फोर्स मौके पर पहुंच जांच की। घायल को पास की निजी अस्पताल में भर्ती कराकर प्राथमिक उपचार कराया गया।

पीड़ित की तहरीर पर रात में ही रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। अचलगंज थानाक्षेत्र के हुलास खेड़ा निवासी शिवम राजपूत (22) सदर कोतवाली के बाबाखेड़ा के पास जन सेवा केंद्र चलता है। सोमवार रात करीब 10:30 बजे वह दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहा था। उसकी दुकान से करीब 400 मीटर दूर पहले से खड़े सफेद अपाचे बाइक सवार तीन बदमाशों ने उसे रोका और बिना कुछ बात किए पीटने लगे।

पीड़ित के मुताबिक उसमें से एक यह बोल रहा था कि यही है यही है। लेकिन जब पीटने का कारण पूछा गया, तो बदमाशों ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद में बैग में पड़े 1.50 लाख रुपए, एटीएम और क्रेडिट कार्ड लेकर बदमाश अचलगंज की ओर भाग निकले। सूचना पर एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना, एएसपीपी उत्तरी अखिलेश सिंह, सीओ सदर सोनम सिंह, सीओ बीघापुर ऋषिकांत शुक्ला मौके पर पहुंचे।

मारपीट और लूट की रिपोर्ट दर्ज

पीड़ित को पास के निजी अस्पताल में इलाज कराया और बयान दर्ज किए। पीड़ित के पास इतने रुपये कहां से आए फिलहाल वह अभी इसका जवाब नहीं दे पाया है। तहरीर के आधार पर रात में ही अज्ञात के खिलाफ मारपीट और लूट की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। घटना के खुलासे के लिए सर्विलांस, एसओजी, सीओ और कोतवाल को लगाया गया है।

जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आज महिला चिकित्सालय सीतापुर का किया औचक निरीक्षण

अवध की आवाज ब्यूरो

सीतापुर। सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आज महिला चिकित्सालय सीतापुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं एवं आवश्यक दिशा–निर्देश संबंधित को दिये। जिलाधिकारी महोदय ने आयुष्मान वार्ड, सिक न्यू बार्न केयर यूनिट आदि वार्डों को देखा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका से चिकित्सकों की जानकारी लेते हुये निर्देशित किया कि ओ0पी0डी0 वार्ड में महिलाओं के बैठनें हेतु उचित

ओ0पी0डी0, हेल्पडेस्क, जे0एस0वाई0 रूम, कैंटीन, ओ0टी0 रूम, लेबर रूम, पैथालॉजी, अल्ट्रासाउण्ड सेंटर, व्यवस्था की जाये। पुरूषों को ओ0पी0डी0 वार्ड से बाहर रखा जाये। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रकरण हैं, उनको रजिस्टर में अंकित करते हुये उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सभी आशाओं को उपलब्ध कराते हुये निस्तारित की जाये। जननी सुरक्षा योजना का लाभ महिलाओं को भर्ती के समय ही पासबुक व आधार कार्ड उनसे ले लिया जाये ताकि उनका इस योजना लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी को परेशान न किया जाये।

जिलाधिकारी ने कहा कि होमगार्ड की मांग कर ली जाये ताकि कोई अव्यवस्था उत्पन्न न होने पाये। निरीक्षण के दौरान महिलाओं को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता परखी तथा निर्देशित किया कि भोजन की गुणवत्ता एवं पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा गुणवत्ता पर लापरवाही करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने दवाओं की जानकारी लेते हुये निर्देशित किया कि दवाओं की उपलब्धता निरन्तर बनाये रखें। महिलाओं व बच्चों को दिये जाने वाले टीकाकरण की जानकारी ली। उन्होंने पैथालॉजी का निरीक्षण करते हुये निर्देश दिये कि जांच हेतु मरीजों का ब्लड ले लिया जाये ताकि जांच के लिये किसी को बाहर न जाना पड़े। अल्ट्रासाउण्ड सेंटर का निरीक्षण करते हुये निर्देश दिये गये कि आये हुये गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउण्ड किया जाये तथा पुरूष का प्रवेश अल्ट्रासाउण्ड सेंटर के अन्दर पूर्णतया निषेध रखा जाये। टीकाकरण कक्ष का निरीक्षण करते हुये अभी तक किये गये टीकाकरण की जानकारी ली। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका को निर्देश दिये कि चिकित्सालय में जो भी कमियां हैं, उनको दुरूस्त कराया जाये तथा निरन्तर साफ–सफाई की जाये। आयुष्मान वार्ड का निरीक्षण करते हुये कहा कि यहां पर बेडों की संख्या बढ़ायी जाये। सिक न्यू बार्न केयर यूनिट के निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि यहां पर चिकित्सकों की उपलब्धता हमेशा बनी रहे तथा सभी आवश्यक दवाएं व उपकरण उपलब्ध रहें। निर्माणाधीन सिक न्यू बार्न केयर यूनिट का भी निरीक्षण करते हुये निर्देश दिये कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। ओ0टी0 रूम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका से जानकारी भी ली तथा अब तक किये गये ओ0टी0 की जानकारी लेते हुये रजिस्टर का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 हरपाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

रिक्त चल रही ग्राम पंचायतो में प्रधान पद के उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन पत्र।

अवध की आवाज ब्यूरो
श्री प्रकाश गुप्ता

सीतापुर। विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायत बिनौरा व डिघिया के प्रधानों का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण ग्राम प्रधानों के स्थान रिक्त चल रहे थे। जिससे दोनों ग्राम पंचायतो में पुनः चुनाव कराने हेतु निर्वाचन अधिकारी अमिताभ वर्मा की उपस्थिति में प्रधान पद के सभी उम्मीदवारों ने आज अपना–अपना नामांकन पत्र दाखिल किया हैं। वहीं ग्राम पंचायत बिनौरा से जमीला पत्नी जमाल , जलालुद्दीन पुत्र इद्दू , मुनीष पुत्र आरिफ, मुहीर पुत्र अशरफ, सुजीत कुमार पुत्र प्रदीप सहित पांच लोगों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं ग्राम पंचायत डिघिया से पूनम देवी पत्नी स्वर्गीय राकेश वर्मा, हिमांक शेखर पुत्र शिवराम यादव, रमांकशेखर पुत्र शिवराम यादव सहित तीन लोगों ने प्रधान पद के लिए अपना–अपना नामांकन दाखिल किया हैं।

हेल्का नम्बर दो में तैनात दरोगा की कार्य शैली क्षेत्र में बनी चर्चा का विषय

अवध की आवाज ब्यूरो

सीतापुर। मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जालेपारा निवासी गयाप्रसाद पुत्र रामलोटन व सुशील कुमार कश्यप पुत्र रामनाथ ने तहसील समांधान दिवस अधिकारी को शपथ पत्र पर एक शिकायत देकर आरोप लगाया है। कि गांव में स्थित तालाब का पट्टा उनके चाचा गया प्रसाद पुत्र भरोसे के नाम है। इस तालाब में वह सिंघाड़ा आदि डालकर अपने परिवार की गुजर बसर करते हैं। पीड़ित का आरोप है। कि वह पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है । दिनांक 17 जुलाई को हेल्के में तैनात दरोगा राधेश्याम सिंह आए और उससे यह कहकर हस्ताक्षर करा लिया कि ताजिया का जुलूस निकलना है। जिससे शांति व्यवस्था बनाए रखते हेतु हस्ताक्षर कराए जा रहे है। दूसरे दिन गांव आकर पीड़ित सुशील कश्यप को घर से बुलाया और का तुम्हारे बिरुध्द शिकायत है। उसके बिरोध करने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए काफी मारा पीटा तथा फर्जी मुकदमा लिखकर जेल भेजने की धमकी देते हुए तालाब के निकट भी न जाने की हिदायत दी। और दोनों को थाने बुलाया जब दोनों थाने गए तो दरोगा जी उन्हें पूरा दिन थाने में बैठाए रखने के बाद जाप्ता फौजदारी की धारा 151 में चालान कर दिया । पीड़ितों का आरोप है। कि गांव के ही निवासी कृष्णकांत सिंह पुत्र राजकुमार व रजनीश सिंह पुत्र कृष्णकांत उसके तालाब पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है । उनके ही कहने पर दरोगा राधेश्याम सिंह बिरादरीवाद निभाते हुए नियम विरुद्ध कार्यवाही की है । उनका आरोप है । कि वह इसके पहले कभी कोतवाली नहीं आए हैं। साक्ष्य के तौर पर कोतवाली में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी जा सकती है। इस लिए दोनों सिकायतकर्ताओं ने आज एक हलफनामे पर शिकायत दर्ज कराकर तहसील समांधान दिवस अधिकारी को देकर रस्सी का सांप बनाने वाले दरोगा राधेश्याम सिंह के बिरुध्द सख्त कार्यवाही की मांग की हैं।

व्यापारी बोले, बजट आम आदमी के हित में,कैंसर की दवा सस्ती होने से मरीज को मिलेगी राहत

लखनऊ। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इसे आम लोगों के हित में बताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल, राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष रिपन कंसल, प्रदेश संगठन मंत्री जावेद बेग, प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेश छबलानी, युवा प्रदेश महामंत्री आकाश गौतम ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट मध्यम वर्ग के लिए नई आशा लेकर के आया है। इस बजट से आयकर में भी छूट मिल रही है और जीवन उपयोगी वस्तुओं जिसमें कैंसर की दवा ऑक्सीजन मोबाइल चार्जर यहां तक की सोना, चांदी भी कुछ सस्ते होंगे। बंसल ने कहा की मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख किए जाने का लाभ छोटे उद्योगों और व्यापारियों को मिल सकता है। ऐसे लोग नए काम शुरू कर सकते हैं। छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार किया गया है। चार लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 500 बड़ी कंपनियों में यह भी बेरोजगारी घटाने में एक बड़ा निर्णय साबित होगा हमें सभी क्लस्टर में सिडबी की नई शाखाएं खोली जाएंगी जिससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा देश में 12 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने का निर्णय भी उत्साहवर्धक है। रसायन पर भी हयात शुल्क घटेगा सौर ऊर्जा से जुड़े पैनल और संबंधित उपकरण पर भी कर घटाया गया है इस प्रकार ई–कॉमर्स पर एक प्रतिशत की जगह दशमलव .1ः कर लगेगा। प्रवेश कर को पूर्णता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। नई सामाजिक सुरक्षा योजना लाई गई है और पारिवारिक पेंशन योजना बढ़ने से निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा। यह बजट देश की आम जनता के लिए उपयोगी किसानों महिलाओं शिक्षा कृषि और उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने वाला बजट है।

बोल बम के जयकारों से गूंज उठे शिवालय।

महिला, पुरुष और बच्चो ने कांवड़ चढ़ाकर महादेव का किया जलाभिषेक।

अवध की आवाज ब्यूरो

सीतापुर। मिश्रिख श्रावण मांस के पहले सोमवार पर तहसील क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरो में हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक रुद्राअभिषेक, सहित विभिन्न अनुष्ठानों से पूजा अर्चना की । सभी शिवालय भोर से ही हर–हर महादेव व बोल बम के जयकारों से गूंजने लगे थे। तहसील क्षेत्र के कस्बा मिश्रित में सीताकुंड तीर्थ पर माता सीता जी व्दारा स्थापित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर , शेषनाथ महादेव मंदिर, दधीचि कुंड तीर्थ पर स्थित दधीचेश्वरनाथ महादेव मंदिर , उत्रेश्वरनाथ महादेव मंदिर , दक्षिणेश्वरनाथ महादेव मंदिर, ग्राम जसरथपुरपुर में स्थित भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर , रामेश्वर महादेव मंदिर में सैकड़ो शिव भक्तों ने कावड़ चढ़ाकर महादेव का जलाभिषेक किया। रविवार की देर रात से ही कावंरियों का जत्था शिवालयों में जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेने रवाना हो गया था। सोमवार की सुबह से ही मंदिरों के घंटे बजने शुरू हो गए। भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं एवं बच्चों ने बोल बम जयकारों के साथ शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करके जलाभिषेक किया। और मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। श्रावण मांह के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मार्गो और मंदिरों पर पुलिस व्दारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम बने रहे।

ट्यूबवेल आपरेटर पदों को तत्काल विज्ञापित करने को लेकर आयोग पर छात्रों ने किया प्रदर्शन

लखनऊ। युवा मंच के बैनर तले छात्रों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में शांतिपूर्ण ढंग से धरना–प्रदर्शन कर सिंचाई विभाग में रिक्त पड़े 9700 से ज्यादा ट्यूबवेल आपरेटर पदों को तत्काल विज्ञापित करने का मुद्दा उठाया। 2016 के बाद से ट्यूबवेल आपरेटर की भर्ती न होने से बड़े पैमाने पर पद खाली हैं और तमाम ट्यूबवेल आपरेटर की कमी से बंद हैं और सिंचाई का काम प्रभावित हो रहा है। युवा मंच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ई. आर. बी. पटेल की अगुवाई में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल की आयोग सचिव से वार्ता हुई जिसमें उन्होंने अधियाचन प्राप्त होने और पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होने का आश्वासन दिया। लेकिन उनके इस आश्वासन पर छात्र संतुष्ट नहीं दिखे क्योंकि आयोग सचिव द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि विज्ञापन कितने दिनों तक जारी होगा और पदों की संख्या क्या होगी। सचिव से वार्ता उपरांत छात्रों ने सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से उनके आवास पर ज्ञापन सौंपा। लेकिन उन्होंने किसी तरह का आश्वासन छात्रों को नहीं दिया। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को भी एक्स हैंडल पर पोस्ट कर ट्यूबवेल आपरेटर भर्ती का मुद्दा उठाया। उनके संज्ञान में यह भी लाया गया कि तकनीकी संवर्ग में एक लाख रिक्त पद हैं उन्हें तत्काल भरने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस मौके पर युवा मंच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व तकनीकी संवर्ग प्रमुख प्रतिनिधि ई. आर.बी. पटेल, जितेन्द्र कुमार, स्वत्रंत कुमार, राजीव सिंह, रामकेश पाल, सुर्दशन उर्फ नीरज पटेल, रितेश पाल, विद्यानंद पटेल, शिवम, सूरज कुमार, रिंकू मौर्या, सौरभ पांडे, सचिन यादव, रामकुमार, बैजनाथ, राकेश, राजीव सिंह, सुमित कुमार, रितेश कुमार, इंद्रजीत, संदीप निराला, मिथुन कुमार, इसरार अहमद, आलोक सिंह, विष्णु चौरसिया इत्यादि लोग शामिल रहे।

लखनऊ पहुंचा एल्विश यादव, ईडी करेगी पूछताछ,

जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारी किया है नोटिस

लखनऊ। यूट्यूबर एल्विश यादव से मंगलवार को ईडी के जोनल ऑफिस, लखनऊ में पूछताछ की जाएगी। एल्विश यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच लखनऊ के जोनल ऑफिस में की जा रही है। ईडी ने एल्विश को नोटिस देकर 8 जुलाई को बुलाया था। लेकिन एल्विश ने विदेश यात्रा और अन्य वजहों से समन को स्थगित करने की मांग की थी। इसके बाद एल्विश को 23 जुलाई को पेश होने का नोटिस दिया गया था। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव पर रेव पार्टियों में सांप का जहर देने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने एल्विश पर कार्रवाई की थी। पीपुल्स फॉर एनिमल्स की संस्था ने एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में रेव पार्टी में सांपों का जहर पहुंचाने का आरोप लगाया था। संस्था की

संस्थापक पूर्व सांसद मेनका गांधी हैं। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने संस्थान के साथ एल्विश यादव के एजेंट और सपेरों को सापों का जहर बेचने के बहाने बुलाकर 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में एल्विश ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। हालांकि पुलिस जांच में उसकी संलिप्ता की बात सामने आई थी। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। एल्विश के दोस्त हरियाणा के मशहूर गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया से ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी ने फाजिलपुरिया से लखनऊ ऑफिस में करीब 7 घंटे पूछताछ की थी। असल में फाजिलपुरिया ने अपने एक गाने में सांपों का इस्तेमाल किया था। ईडी ने शक के आधार पर फाजिलपुरिया से पूछताछ की थी। ईडी को शक था कि फाजिलपुरिया को एल्विश ने सांप मुहैया कराया था। इससे पहले एल्विश यादव को 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने पार्टियों में सांप के जहर के इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में अरेस्ट किया था।

गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों पर पानी फेरने वाला बजट : लोकदल

लखनऊ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश किए जाने पर लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस बजट में क्या है? जहां से प्रधानमंत्री जी सांसद चुने गए है। किसानों की एमएसपी की बात इस बजट में क्यों नहीं है। सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है। सरकार ने 4 करोड़ नौकरी की झूठी घोषणा की है। सरकार यह बताए कि पिछले दस साल में कितनी नौकरी दी है। इस बजट में भी किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहा की गई। अडानी–अंबानी को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों के अच्छे दिन' की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन पर पानी फेरने वाला यह बजट है।

6 चोरों के गिरोह ने 200 लग्जरी कारें चुराई,नोएडा पुलिस ने पकड़ा

नोएडा। नोएडा में पकड़े गए 6 वाहन चोर 200 से ज्यादा लग्जरी कारों की चोरी कर चुके है। ये कार नार्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल , महाराष्ट्र में बेची गई। इनका काम ऑन डिमांड चोरी करना था। कम पढ़े लिखे होने के बाद भी टेक्नोलॉजी में इनको महारत हासिल थी। यही वजह थी की केईवाई प्रोग्रामिंग पेड से कार के ईसीएम मशीन को रि प्रोग्राम कर डूप्लीकेट चाबी बनाकर चोरी कर लेते थे। इस काम में महज 5–10 मिनट का समय लगता था। डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया कि गिरोह के बदमाशों के ऊपर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के अलग–अलग थानों में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह के बदमाशों ने अब तक 200 से अधिक चार पहिया वाहनों की चोरी दिल्ली–एनसीआर समेत अन्य राज्यों में की है। गिरोह का पर्दाफाश करने वाली टीम को डीसीपी नोएडा ने 25 हजार रुपए का इनाम दिया है। डीसीपी रामबदन सिंह ने बताया कि बीते दिनों सोरखा गांव से एक व्यक्ति की फॉर्च्यूनर चोरी हुई थी। चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वीडियो के आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का खाका तैयार करने लगी। एसीपी थर्ड शैव्या गोयल की अगुआई में 15 पुलिसकर्मियों की एक टीम गठित की गई। सोमवार को गिरोह के बदमाश जब दोबारा चोरी करने के लिए नोएडा की सीमा में दाखिल हुए तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आया राजेश कक्कड़ चोरी के वाहनों को खरीदता है और पंजाब ले जाता है। लग्जरी कारों को राजेश 15 से 20 लाख और सामान्य कारों को तीन से सात लाख रुपए में बेच देता है। ज्यादातर गाड़ियां नार्थ ईस्ट में सप्लाई की जाती है। राजेश कई अन्य गिरोह से भी चोरी के वाहन को खरीदता है। राजेश के पड़ोसियों ने बताया कि उसके दोनों बेटे कनाडा में रहते हैं और चोरी के वाहनों को खरीदने और कुख्यात वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को फंडिंग करने का काम वह बीते दस साल से कर रहा है। उसका नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। एसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि पकड़ा गया खलील पांचवी, मोनू दसवीं, सोनू और राजेश आठवीं, प्रमोद 12वीं पास है। अली शेर उर्फ इमरान अनपढ़ है। गिरोह के सरगना सोनू को वाहनों के पुर्जों की अच्छी समझ है। वह किसी भी वाहन का लॉक चंद सेकेंड में तोड़ देता है।

डीसीपी ने बताया कि बदमाशों के खिलाफ धारा–111 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। यह धारा पूर्व की गैंगस्टर की धारा के समकक्ष है। धारा 111 संगठित अपराध करने और उसे बढ़ावा देने वाले आरोपियों पर लगाई जाती है। बताया जा रहा है नए कानून के बाद नोएडा पुलिस द्वारा दबोचा गया यह पहला गिरोह है जिसके सदस्यों के खिलाफ धारा–111 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि गिरोह के सदस्य हाईटेक तरीके से वाहनों की चोरी करते हैं। इनके पास की– प्रोग्रामिंग पैड होता है जिसे ये ऑनलाइन मंगवाते है। आरोपी की– प्रोग्रामिंग पैड का इस्तेमाल कर ईसीएम (इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट मैनेजमेंट) मशीन को रिप्रोग्राम कर लेते हैं। इससे पूरी गाड़ी इनके नियंत्रण में आ जाती है। आरोपी अपने पास गाड़ियों का लॉक तोड़ने और नकली चाबी बनाने के उपकरण भी रखते हैं। चाबियों का गुच्छा भी इनके पास रहता है। इससे आरोपी आसानी से वाहनों की चोरी कर लेते हैं।गिरोह के सदस्य चोरी के वाहनों की नंबर प्लेट तुरंत बदल देते थे और वाहन को दो से तीन दिन के लिए किसी सुनसान जगह पर खड़ा कर देते थे। इसके बाद चोरी की गाड़ियों की फर्जी आरसी व नंबर प्लेट तैयार करने के बाद बार्डर पार कराते थे। इस दौरान यदि कही पुलिस चेकिंग हो जाए तो ये अपने आप को मैकेनिक बताकर वहां से निकल जाते थे। इनके पास कार से संबंधित सभी उपकरण होते थे। इसलिए इन पर ज्यादा शक नहीं होता था। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो पहले गाड़ी के मैकेनिक का काम भी कर चुके हैं।

100 मेडिकल छात्र-छात्राओं को बांटे गए टैबलेट

उरई/जालौन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेधावी छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल का वितरण किया जा रहा है। जिससे उन्हें भविष्य में पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं का भी लाभ ले सकें। इसी के तहत जालौन के उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक एमबीबीएस के छात्र–छात्राओं को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह ने टैबलेट का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टैबलेट के माध्यम से एमबीबीएस के छात्र–छात्राओं को पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। जिन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने एमबीबीएस प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष के सभी छात्र–छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार छात्र–छात्राओं के हित में काम कर रही है। उन्हें पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए मेधावी छात्र–छात्राओं के साथ उन्हें भी टैबलेट दे रहे हैं। जो इसे खरीदने में अक्षम है। टैबलेट के माध्यम सभी छात्र–छात्राएं सरकार की चलाई जाने वाली योजना और रोजगार के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। टैबलेट में सभी योजना छात्र छात्राओं के हित बारे में है। वह कौशल विकास योजना तथा अन्य योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा छात्र छात्राएं टैबलेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। वहीं उरई विधायक गौरी शंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन ने भी सरकार की इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उपस्थित छात्राओं को अवगत कराते हुए कहा कि सरकार छात्रों के हित में लगातार अच्छा काम कर रही है। निर्धन छात्र–छात्राओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जिससे उन्हें पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या न हो।

डीएम ऑफिस पर किसानों का प्रदर्शन,बिजली कटौती की समस्या से निजात दिलाने की मांग

उरई/जालौन। जालौन में मंगलवार को बिजली समस्या को लेकर भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले प्रांत अध्यक्ष साहब सिंह चौहान के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने उरई के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए एडीएम नमामि गंगे विशाल यादव के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि यदि समस्याओं का निदान नहीं किया जाता है, तो किसान अनिश्चितकालीन धरना–प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले उरई कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रांत अध्यक्ष साहब सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सक्सेना जिला मंत्री आनंद द्विवेदी, रामबाबू सिंह, विष्णु कांत, लक्ष्मी नारायण, कृष्ण कुमार, अरविंद कुमार, शीलू पाल, विश्राम सिंह चौहान, रामबाबू, राम आसरे सहित दर्जनों किसानों ने उरई के कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया।इस मौके पर डीएम कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि जनपद में खरीफ की फसल की बुवाई हो चुकी है, धान रोपी जा चुकी है, मगर बिजली विभाग द्वारा लगातार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे धान सूखने की कगार पर है, नहर में पानी नहीं आ रहा है, जिस कारण पंप रखकर भी किसान धान में पानी नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे मिट्टी सूख रही है, इतना ही नहीं बिजली सब स्टेशनों की क्षमता और संबंधित लाइनों की समीक्षा की जाए। किसानों ने कहा कि जिन स्टेशनों पर असमान लोड है, उसको समान रूप से समीप सब स्टेशनों से जोड़ा जाए एवं खकसीस सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाई जाए, इतना ही नहीं आए दिन फाल्ट के नाम पर बिजली कटौती की जा रही है, इसमें सुधार लाया जाए और जहां की लाइन जर्जर हो चुकी है, उन्हें बदलवाया जाए, जिससे किसान अपनी फसल को सूखने से बचा सके। वहीं जिन सब स्टेशनों पर भार नहीं है, उन सब स्टेशन भारी भार वाले क्षेत्र से जोड़ा जाए, जिससे बिजली कटौती न हो। वही नहर का संचालन भी अभिलंब कराया जाए, जिससे किसान धान की फसल में पानी लगा कर सके।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग की होगी जांच,गड़बड़ी मिलने पर नोटिस जारी होगा, 10 हजार का जुर्माना लगेगा

नोएडा। नोएडा हाइराइज इमारतों का शहर है। यहां वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है। आगामी 10 साल में ग्राउंड वाटर लेवल की स्थिति खराब हो सकती है। औसतन सालाना डेढ़ से दो मीटर तक वाटर लेवल गिर रहा है। जिससे यहां पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। इसे कंट्रोल करने के लिए भवन नियमावली के तहत 300 वर्गमीटर और बड़े प्लाट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। ये सिस्टम यहां बनी रिहाइशी इमारत, कॉमर्शियल मॉल, होटल, स्कूल, सरकारी इमारतों में एक्टिव है या नहीं इसकी पड़ताल की जा रही है। नोएडा प्राधिकरण के पर्यावरण सेल ने इसके लिए दो टीम गठित की है। ये टीम चार दिन में नोएडा के सभी श्रेणी की प्रॉपर्टी पर जाकर रैंडम जांच करेगी। पहले चरण में 10–10 स्थानों पर जाएंगी। इसकी एक रिपोर्ट सीईओ नोएडा प्राधिकरण को दी जाएगी। जिस स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मानकों पर काम करता नहीं पाया जाएगा। वहां नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस की समय 15 दिन का होगा। 16वें दिन प्रॉपर्टी मालिक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 17वें दिन में रोजाना 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। नोएडा प्राधिकरण में पर्यावरण सेल के सलाहकार गुंजन मिश्रा ने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जांच के लिए आदेश मिल गया है। इसकी प्रति प्राधिकरण के सभी वर्क सर्किल और सभी आरडब्ल्यूए और एओए को जारी कर दी गई है। एओए और सेक्टर के आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने यहां स्वयं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जांच कराकर रिपोर्ट सब्मिट करे।देखा जाए तो जनपद गौतमबुद्ध नगर में शुरुआती दौर में 1,018 तालाब थे। इसमें 67 तालाब नोएडा प्राधिकरण, 281 ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र और 277 तालाब यमुना विकास प्राधिकरण और करीब 361 तालाब ग्राम पंचायत क्षेत्र में है। विगत एक साल में तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में कई तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया। जिसमें से 217 के करीब तालाबों पर अतिक्रमण था। जिसमें नोएडा में 40 तालाब शामिल है।

कुएं में मिला बुजुर्ग का शव,4 दिनों से था लापता

बांदा। जनपद में एक घर से 4 दिन से लापता वृद्ध का शव कुएं के पानी में उतरता हुआ मिला। ग्रामीणों ने जैसे देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा के पलानी थाना क्षेत्र के सिंधन कला गांव के मजरा पडवन डेरा के रहने वाले रामधनी (70) चार दिन पहले घर से शौच के लिए निकले थे। उसके बाद वह घर नहीं लौटे तो घर वाले तलाश करने लगे। जब चरवाहों ने डेरा के बाहर बने कुएं में एक शव उतराता हुआ दिखा तो उसने तुरंत रामधनी के घरवालों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने परिजनों को मदद से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। उसके छोटे बेटे अमरजीत ने बताया कि वह दो भाई है और घर में मां है। पिता को आंखों से कम दिखाई देता था। उसी की वजह से हादसा हुआ है। पैलानी थाना प्रभारी आनंद कुमार ने बताया कि कुएं के अंदर शव मिलने की जानकारी मिली थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची शव को कब्जे में ले लिया गया है।

कृष्ण कुमार ने दी अपनी इकलौती बेटी को मुखाग्नि, तस्वीरें बयां कर रही तिशा के माता-पिता का दर्द

अभिनेता–निर्माता कृष्ण कुमार की बेटी और टी–सीरीज के चेयरपर्सन भूषण कुमार की चचेरी बहन तिशा कुमार का 18 जुलाई को 20 साल की उम्र में निधन हो गया। कथित तौर पर लंबी बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तिशा कुमार का अंतिम संस्कार आज किया गया जहां मनोरंजन उद्योग की कई हस्तियां शामिल हुई।

भूषण कुमार और दिव्या खोसला से लेकर रितेश देशमुख, फराह खान, साजिद खान, जावेद जाफरी और कई अन्य तिशा को अंतिम विदाई देने पहुंचे। इस दौरान तिशा के माता– पिता का हाल देख हर किसी की आंखें नम हो गई। एक जवान बेटी को खोने का दर्द अकल्पनीय है। यह वही समझ सकता है जिसने कभी अपनों को खोया है।

दरअसल तिशा का अंतिम संस्कार मुंबई स्थित विले पार्ले श्मशान में रविवार शाम 5 बजे होना था, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को लेकर आ रही फ्लाइट को भारी बारिश के कारण अपना रूट बदलना पड़ा। इसके बाद कृष्ण कुमार और तान्या सिंह ने बेटी का अंतिम संस्कार आज करने का फैसला किया। इस दौरान कई दिल दुखा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें कृष्ण कुमार और उनकी पत्नी बेहद बुरी हालत में नजर आ रहे हैं।अपनी इकलौती बेटी तिशा कुमार के अंतिम संस्कार में पिता कृष्ण कुमार फूट–फूटकर रोए। वहीं तान्या सिंह बेसुध हो गई जिन्हें परिवार वालों ने बेहद मुश्किल से संभाला। अपनी कजिन बहन तिशा कुमार को अंतिम विदाई देने पहुंची खुशाली और तुलसी कुमार के चेहरे पर भी उदासी साफ नजर आ रही थी। दिव्या खोसला भी अपनी ननद तिशा कुमार को अंतिम विदाई देने पहुंची थी। 'तिशा करीब तीन साल से कैंसर से पीड़ित थीं। वह कुछ दिन पहले ही बेहतर इलाज के लिए जर्मनी गई थीं जहां के अस्पताल में उन्होंने अंतिम श्वांस ली। तिशा टी–सीरीज के प्रमुख भूषण कुमार की भतीजी थीं। उनके पिता कृष्ण कुमार ने 1990 के दशक में बेवफा सनम और कसम तेरी कसम जैसी फिल्मों में अभिनय किया।

अगर मैं बिग बी के साथ काम कर रहा होता, तो भी मुझे दबाव महसूस नहीं होता : लक्ष्य खुराना

टीवी सीरियल इश्क जबरिया में एक्टर लक्ष्य खुराना आदित्य का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना रहे हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस

शेयर किया और डर व दबाव के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। अपने एक्सपीरियंस पर बात करते हुए, लक्ष्य ने कहा, इश्क जबरिया मेरा आठवां शो है, और इस प्रोजेक्ट के जरिए मुझे काम्या पंजाबी और प्रणति प्रधान जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला है। सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने के चलते, मुझे कोई दबाव महसूस नहीं होता। एक्टर ने कहा, सेट पर, हम अपने किरदारों में पूरी तरह डूब जाते हैं और अपनी लाइंस और सींस पर फोकस करते हैं। जबकि कुछ एक्टर सीनियर के साथ काम करने से डर महसूस करते हैं। मैं इसे सीखने के अवसर के रूप में देखता हूं। लक्ष्य ने कहा, अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा होता, तो भी मुझे दबाव महसूस नहीं होता। मेरा मानना है कि एक्सपीरियंस होल्डर एक्टर्स से सीखने के लिए बहुत कुछ है, और उनकी मौजूदगी मुझे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। इश्क जबरिया बिहार के बेगूसराय में सेट एक रोमांटिक ड्रामा है, जो गुलकी (सिद्धि शर्मा) के बारे में है। वह खुशमिजाज और जिंदादिल लड़की है। वह एयर होस्टेस बनना चाहती है, लेकिन उसकी सौतेली मां उसके इस सपने को पूरा होने में बाधा बनी हुई है। तमाम रुकावटों के बाद भी गुलकी कभी उम्मीद नहीं खोती। इस शो में काम्या पंजाबी, सिद्धि और लक्ष्य हैं। पहली बार पॉजिटिव रोल निभाने पर लक्ष्य ने कहा, मेरे लिए निगेटिव रोल निभाना पॉजिटिव किरदार से कहीं ज्यादा आसान है। निगेटिव रोल में, मेरे पास करेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ होता है। एक्टर ने कहा, पॉजिटिव रोल निभाते समय मुझे बहुत सावधान होना पड़ता है, खासकर उन सींस में जहां मुझे गुस्सा दिखाना होता है। हमेशा यह डर रहता है कि अगर मैंने इसे ज्यादा कर दिया तो किरदार निगेटिव लग सकता है। इश्क जबरिया शो सन नियो पर सोमवार से शनिवार शाम 7.30 बजे प्रसारित होता है।

मनोरंजन उद्योग में नेटवर्किंग और रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण : सुम्बुल तौकीर

अपने करियर पर बात करते हुए एक्ट्रेस सुम्बुल तौकीर ने कहा कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की ओर काम कर रही है। काव्या–एक जज्बा, एक जुनूनश में मुख्य भूमिका निभाने वाली सुम्बुल ने बताया, मैं हर अनुभव से सीखने और अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए काम करती हूं। आजकल मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के साथ–साथ अपने काम में भी सुधार लाने की कोशिश कर रही हूं। उन्होंने कहा, ये कौशल मुझे बेहतर प्रदर्शन करने और उद्योग में विभिन्न भूमिकाओं और चुनौतियों के लिए लचीला बने रहने में मदद करते हैं। एक्ट्रेस को लगता है कि मनोरंजन उद्योग में सामाजिक होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नए कनेक्शन और संपर्क बनाने में मदद मिलती है। सुम्बुल ने बताया, मनोरंजन उद्योग में नेटवर्किंग और रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें नए अवसरों और सीखने की ओर ले जाते हैं। मुझे लगता है कि यह केवल संपर्क बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि रिश्तों को स्वीकार करने के बारे में भी है। एक्ट्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि मनोरंजन उद्योग में तालमेल बैठाना बेहद ही आवश्यक है क्योंकि यहां चीजें तेजी से बदलती हैं। उन्होंने कहा, मैं नए विचारों के साथ खुला रहना चाहती हूं, लगातार अपने कौशल में सुधार करना चाहती हूं और अलग–अलग भूमिकाएं और चुनौतियां लेना चाहती हूं। मुझे पता है कि असफलताएं यात्रा का हिस्सा हैं, लेकिन मैं उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों के रूप में देखती हूं। मुझे लगता है कि मजबूत बने रहने और अपने लक्ष्यों और विश्वासों को ध्यान में रखते हुए मैं और भी मजबूती से वापसी कर सकती हूं। मनोरंजन उद्योग बहुत प्रतिस्पर्धी है, और सुम्बुल इस बात से सहमत हैं। एक्ट्रेस ने कहा, प्रासंगिक बने रहना कठिन हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा सुर्खियों में बने रहने के दबाव के बजाय अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती हूं। मैं अच्छा काम और सार्थक प्रोजेक्ट लेकर अपने लिए एक स्थायी करियर बनाना चाहती हूं। अंत में मुझे लगता है कि यह सब वास्तविक होने, महत्वाकांक्षी बने रहने और अपने काम को बोलने देने के बारे में है।

अरमान–कृतिका मलिक के अश्लील वीडियो पर बिग बॉस ओटीटी 3 मेकर्स का जवाब, कहा–क्लिप से की गई छेड़छाड़

कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 3 एक बार फिर विवादों में है। अश्लील वायरल वीडियो के मामले पर मेकर्स ने मंगलवार को जवाब दिया। दरअसल, बिग बॉस के घर से यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें दोनों इंटीमेट होते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर मेकर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। रियलिटी शो के मेकर्स ने अपने जवाब में कहा कि इस वीडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है, यह फर्जी है। मेकर्स ने बिग बॉस ओटीटी और जियो सिनेमा के खिलाफ इस तरह के अश्लील कंटेंट बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे ने मुंबई पुलिस आयुक्त से अश्लीलता के चलते शो को तुरंत बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को प्रसारित एपिसोड में कंटेस्टेंट को अश्लील और आपत्तिजनक हरकतें करते हुए दिखाया गया। कायंदे ने कहा, इस शो को बच्चे भी देखते हैं। इसलिए इस शो को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। शो के प्रोड्यूसर्स और कंपनी के सीईओ के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। इस मामले की जांच के लिए पुलिस आयुक्त से लिखित अनुरोध किया गया है। मंगलवार को, जवाब में, जियो सिनेमा के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, जियो सिनेमा प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाने वाले किसी भी कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस का पालन करता है। बिग बॉस ओटीटी में ऐसा कोई कंटेंट नहीं था। वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में अश्लीलता शामिल करने के लिए उससे छेड़छाड़ की गई है। यह फर्जी है। हम जियो सिनेमा की इंटीग्रिटी और दर्शकों के भरोसे को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस फर्जी क्लिप का क्रिएशन और सर्कुलेशन गंभीर चिंता का विषय है। हमारी टीम जांच कर रही है और शबिग बॉस ओटीटीश और जियोसिनेमा के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक कंटेंट बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगी। बिग बॉस ओटीटी 3 को अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं। शो में इस समय एक्टर रणवीर शौरी, साई केतन राव, सना मकबूल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लवकेश कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी कुमार, कपल अरमान मलिक और कृतिका मलिक व नेजी कंटेस्टेंट्स के तौर पर दिखाई दिए। बिग बॉस ओटीटी 3 रात 9 बजे जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होता है।

आईएमडीबी 2024 की सबसे पॉपुलर इंडियन फिल्मों की लिस्ट में कल्कि 2898 एडी टॉप पर

साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी को रिलीज हुए लगभग एक महीने पूरा होना वाला है, लेकिन इसका क्रेज लोगों पर अभी भी बरकरार है। इस फिल्म को लगातार सफलता मिल रही है। अब इस फिल्म ने 2024 की अब तक की सबसे पॉपुलर इंडियन फिल्मों की आईएमडीबी लिस्ट में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पटानी समेत कई कलाकारों ने अहम रोल निभाया है। वहीं नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है। डायरेक्टर नाग अश्विन ने कहा, ष्हमारी पूरी टीम के लिए आईएमडीबी लिस्ट में शामिल होना बहुत खुशी और सम्मान की बात है। मुझे लगता है कि यह सीधे तौर पर दुनिया भर में हमारे दर्शकों के प्यार को दर्शाता है। यह हमें सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा स्थान मलयालम फिल्म मंजुम्मेल बॉयज ने हासिल किया। फिल्म में सोबिन शाहिर, श्रीनाथ भासी, बालू वर्गीज, गणपति एस. पोडुवल, लाल जूनियर, दीपक परम्बोल, अभिराम राधाकृष्णन, अरुण कुरियन, खालिद रहमान और शेबिन बेंसन लीड रोल में हैं। यह फिल्म 2006 में

तमिलनाडु के कोडाइकनाल में हुई सच्ची घटना पर आधारित है। मंजुम्मेल बॉयज ग्रुप कोडाइकनाल में छुट्टियां मनाने पहुंचता है। वहां वह मशहूर गुफाओं में जाते हैं। ये गुफाएं कमल हासन की फिल्म श्गुनाश से लोकप्रिय हुई थीं।

नशे में धुत और फुल–ऑन एक्साइटमेंट के चलते सभी खतरनाक चेतावनियों को नजरअंदाज कर एक गहरे गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। इस दौरान एक दोस्त सुभाष गड्ढे में गिर जाता है। अब अपने साथी को बचाने के लिए सभी एकजुट हो जाते हैं। मंजुम्मेल बॉयज के निर्देशक चिदंबरम ने कहा मंजुम्मेल बॉयज दोस्ती और एक सर्वाइवल थ्रिलर की कहानी है, जो जिंदगी की जंग और दोस्ती की कहानी को आगे ले जाती है। फिल्म का विजुअल स्टोरीटेलिंग ग्लोबल ऑडियंस को पसंद आया। यह फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। दर्शकों से मिले प्यार और जबरदस्त प्रतिक्रिया को देख मैं काफी खुश हूं। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर लिस्ट में तीसरे स्थान पर रही, उसके बाद श्हनु मानश, श्शैतानश और लापता लेडीज का स्थान रहा। लिस्ट में अन्य फिल्मों में आर्टिकल 370, प्रेमलु, आवेशम और मुंज्या शामिल हैं। आईएमडीबी की साल के बाकी समय की सबसे प्रतीक्षित भारतीय फिल्मों की लिस्ट में भूल भुलैया 3, थंगालान, औरों में कहां दम था और स्त्री 2 शामिल हैं।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सैक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com

R.N.I.- UPHIN/2012/45127

नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।